(घ) चूंकि आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित राशि के बारे में बताना अभी समयपूर्व होगा। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव गैर-योजनागत निधियों में से किया जाता है और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर वर्ष दर वर्ष धनराशि आवंटित की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक आवासों, होटलों और यात्री-निवासों का निर्माण

250 **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश में जिला-वार बनाए गए पर्यटक आवासों, होटलों, और यात्री-निवासों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) ये होटल आदि किन-किन स्थानों पर हैं और इसके लिए उन्हें कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) इस समय केंद्रीय सरकार के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए प्रस्ताव हैं; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (**श्री माधवराव सिंधिया**) : (क) और (ख) केंद्रीय पर्यटन विभाग ने गत पांच वर्षों के दौरान पर्यटक होटलों या होस्टलों का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को वित्तीय सहायता नहीं दी है । तथापि, इलाहाबाद में एक यात्री निवास तथा माल्वीपुर में एक अन्य यात्री निवास के लिए वित्तीय सहायता (स्वीकृत राशि क्रमशः 29.42 लाख और 40.20 लाख रुपए) दी गई है ।

(ग) और (घ) 1991–92 के दौरान , अयोध्या और चित्रकूट में दो यात्री निवासों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुसूचों सहित विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं ।

उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में नई सूती मिलें

251. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सहकारी क्षेत्र में राज्यवार कितनी सूती मिलें हैं ;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और विद्युत-चालित करघा उद्योगों की मांगों को पूरा करने में सक्षम हैं ;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, कानपुर एवं सुलतानपुर जिलों में नई मिलों की स्थापना करने का कोई विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की कितनी मिलें स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री यशोक गहलोत) : (क) संलग्न विवरण में दी गई सूची के अनुसार मिलों की संख्या 120 है । (नीचे देखिए) ।

(ख) सहकारिता क्षेत्र की मिलों के अलावा हथकरघा तथा विद्युत करघा उद्योग की मांग अन्य क्षेत्रों तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों आदि द्वारा भी पूरी की जाती है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, और सुलतानपुर में नई मिल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

30 सितम्बर, 91 की स्थिति के अनुसार, सहकारिता क्षेत्र में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों तथा फब्रिक बुनाई एककों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य	सहकारिता मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
असम	1